

EXAM GENIUS

Presents

GENIUS CURRENT AFFAIRS

In Bilingual

27 June 2026



UPSC



SSC



BANK



RAILWAY



STATE EXAMS

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: Which Ministry notified the 10th amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011 in 2026?

प्रश्न: वर्ष 2026 में विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 के 10वें संशोधन को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया?

- A) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- B) Ministry of Law and Justice / विधि एवं न्याय मंत्रालय
- C) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Union Ministry of Home Affairs (MHA) notified the 10th amendment to the Foreign Contribution (Regulation) Rules, 2011, framed under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (FCRA).
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 में 10वां संशोधन अधिसूचित किया, जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA) के अंतर्गत बनाए गए हैं।
- The definition of "Key Functionary" has been expanded to include directors, trustees and all decision-makers, making them personally accountable for any irregularities.
- "मुख्य पदाधिकारी (Key Functionary)" की परिभाषा का विस्तार कर इसमें निदेशक, ट्रस्टी तथा सभी निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्हें किसी भी अनियमितता के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जाएगा।
- NGOs applying for registration must select their objectives from a predefined list of 105 approved activities and specify the States/UTs in which they will operate.
- पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले NGOs को 105 स्वीकृत गतिविधियों की पूर्वनिर्धारित सूची में से अपने उद्देश्य चुनने होंगे तथा जिन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वे कार्य करेंगे, उनका उल्लेख करना होगा।
- NGOs registered before 2026 must inform the government within one year about the States/UTs where they operate and the purposes for which foreign funds are utilized.
- वर्ष 2026 से पहले पंजीकृत सभी NGOs को एक वर्ष के भीतर सरकार को उन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तथा विदेशी धन के उपयोग के उद्देश्यों की जानकारी देनी होगी जहाँ वे कार्यरत हैं।





- Organizations engaged in religious education or cultural preservation must ensure that their activities do not lead to religious conversions.
- धार्मिक शिक्षा या सांस्कृतिक संरक्षण से जुड़े संगठनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियाँ धर्म परिवर्तन का कारण न बनें।
- Foreign nationals who are not of Indian origin cannot hold key positions in NGOs receiving foreign contributions.
- भारतीय मूल के नहीं होने वाले विदेशी नागरिक विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले NGOs में प्रमुख पदों पर नहीं रह सकेंगे।
- Organizations must utilize at least 75% of the foreign funds already received before becoming eligible for the next installment.
- अगली विदेशी सहायता प्राप्त करने से पहले संगठनों को प्राप्त धनराशि का कम-से-कम 75% उपयोग करना होगा।
- NGOs must disclose details of their social media accounts, websites and publications to the government.
- NGOs को अपने सोशल मीडिया खातों, वेबसाइटों एवं प्रकाशनों का विवरण सरकार को देना अनिवार्य होगा।
- The proposed 2026 Bill also provides that if an NGO's registration is cancelled or not renewed, a government-appointed Designated Authority may take control of assets created from foreign funds and dispose of them in the public interest.
- प्रस्तावित 2026 विधेयक के अनुसार यदि किसी NGO का पंजीकरण रद्द हो जाता है या नवीनीकृत नहीं होता, तो सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण (Designated Authority) विदेशी धन से निर्मित संपत्तियों का नियंत्रण लेकर उन्हें जनहित में बेच सकता है।
- For renewal, NGOs must have utilized at least ₹10 lakh of foreign contributions on approved activities during the previous two financial years. Penalties for FCRA violations include a fine of up to 30% of the misused amount or ₹1 lakh, whichever is higher.
- नवीनीकरण के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों में स्वीकृत गतिविधियों पर कम-से-कम ₹10 लाख विदेशी अंशदान का उपयोग आवश्यक होगा। FCRA उल्लंघन पर दुरुपयोग की गई राशि का 30% या ₹1 लाख (जो अधिक हो) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।





Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA) Enacted – 2010
- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) – 2010
- Foreign Contribution (Regulation) Rules Notified – 2011
- विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम अधिसूचित – 2011
- Ministry Responsible – Ministry of Home Affairs (MHA)
- संबंधित मंत्रालय – गृह मंत्रालय (MHA)
- Headquarters of Ministry of Home Affairs – New Delhi
- गृह मंत्रालय का मुख्यालय – नई दिल्ली



EXAM
Genius





Ques: From which date will RBI's new framework against mis-selling by banks come into effect?

प्रश्न: बैंकों द्वारा गलत बिक्री (Mis-selling) रोकने के लिए RBI का नया ढांचा किस तिथि से प्रभावी होगा?

- A) 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026
- B) 1 October 2026 / 1 अक्टूबर 2026
- C) 1 January 2027 / 1 जनवरी 2027
- D) 1 April 2027 / 1 अप्रैल 2027
- E) 1 January 2028 / 1 जनवरी 2028

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has issued the Reserve Bank of India (Responsible Lending Conduct and Customer Protection) Directions, 2026.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट एंड कस्टमर प्रोटेक्शन डायरेक्शंस, 2026" जारी किए हैं।
- The framework aims to prevent mis-selling of financial products such as insurance, mutual funds, loans, and investment products.
- इस ढांचे का उद्देश्य बीमा, म्यूचुअल फंड, ऋण एवं निवेश उत्पादों की गलत बिक्री (Mis-selling) को रोकना है।
- Banks will no longer be allowed to force customers to buy insurance or other financial products as a condition for obtaining a loan.
- अब बैंक ग्राहकों को ऋण लेने के लिए बीमा या अन्य वित्तीय उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे।
- Explicit customer consent will be mandatory through signed declarations, OTP-based approvals, or recorded confirmations.
- हस्ताक्षरित घोषणा, OTP आधारित स्वीकृति या रिकॉर्डेड पुष्टि के माध्यम से ग्राहक की स्पष्ट सहमति अनिवार्य होगी।
- The framework prohibits forced bundling of products and misleading sales practices.
- यह ढांचा उत्पादों की जबरन बंडलिंग और भ्रामक बिक्री प्रथाओं पर रोक लगाता है।
- If mis-selling is established, customers may receive refunds and compensation for losses.
- यदि गलत बिक्री सिद्ध होती है, तो ग्राहकों को धनवापसी और नुकसान की भरपाई मिल सकती है।





Recent News Headlines Related to RBI

- The Reserve Bank of India (RBI) has permitted Indian banks, including their overseas branches, to extend loans against FCNR(B) deposits.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय बैंकों तथा उनकी विदेशी शाखाओं को FCNR(B) जमा के विरुद्ध ऋण देने की अनुमति दी है।
- The Reserve Bank of India has issued the final revised Kisan Credit Card (KCC) Framework.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ढांचा जारी किया है।
- The Reserve Bank of India has exempted banks from maintaining Cash Reserve Ratio (CRR) and Statutory Liquidity Ratio (SLR) on fresh Non-Resident External (NRE) Term Deposits with a maturity of 3 years or more.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों को 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली नई अनिवासी बाह्य (NRE) सावधि जमा पर नकद आरक्षित अनुपात (CRR) और वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) बनाए रखने से छूट दी है।
- The Reserve Bank of India cancelled the licence of Shree Mahalaxmi Urban Co-operative Credit Bank, a Karnataka-based co-operative bank.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक स्थित श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।
- The Reserve Bank of India (RBI) relaxed the capital requirements for banks on loans backed by the Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS 5.0).
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS 5.0) द्वारा समर्थित ऋणों पर बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं में राहत प्रदान की।
- The Reserve Bank of India (RBI), Thiruvananthapuram, launched RBI Reelathon 2026, an awareness campaign aimed at engaging college students in the fight against cyber-enabled financial frauds.
• भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), तिरुवनंतपुरम ने RBI Reelathon 2026 नामक जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य कॉलेज छात्रों को साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक करना है।





Ques: Which company became the first Non-Banking Financial Company (NBFC) to utilize the RBI's subsidised hedging facility for overseas borrowings?

प्रश्न: RBI की विदेशी उधारी के लिए सब्सिडी युक्त हेजिंग सुविधा का उपयोग करने वाली पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) कौन बनी?

- A) Power Finance Corporation (PFC) / पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)
- B) Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) / भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA)
- C) REC Limited / आरईसी लिमिटेड
- D) Rural Electrification Corporation Finance / ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- E) HUDCO / हडको

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Power Finance Corporation (PFC) successfully raised USD 300 million through a 5-year Dollar Bond issue.
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) ने 5-वर्षीय डॉलर बॉन्ड जारी कर 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए।
- PFC became the first Non-Banking Financial Company (NBFC) to utilize the RBI's subsidised hedging facility for overseas borrowings.
- PFC विदेशी उधारी के लिए RBI की सब्सिडी युक्त हेजिंग सुविधा का उपयोग करने वाली पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बन गई।
- A Dollar Bond is a bond issued in US Dollars to raise funds from international investors.
- डॉलर बॉन्ड वह बॉन्ड है जिसे अमेरिकी डॉलर में जारी कर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से धन जुटाया जाता है।
- Dollar Bonds help companies access foreign capital markets, and both repayment and interest are generally made in US Dollars.
- डॉलर बॉन्ड कंपनियों को विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच प्रदान करते हैं तथा इनका मूलधन और ब्याज सामान्यतः अमेरिकी डॉलर में चुकाया जाता है।
- PFC operates under the administrative control of the Ministry of Power and holds Maharatna status.
- PFC विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है तथा इसे महारत्न का दर्जा प्राप्त है।





Ques: Which ministry is set to launch the Index of Services Production (ISP) to measure monthly changes in the growth of India's formal services sector?

प्रश्न: भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में मासिक परिवर्तनों को मापने के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (ISP) किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा?

- A) Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
- B) Ministry of Commerce and Industry / वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
- D) Ministry of Corporate Affairs / कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
- E) Ministry of Labour and Employment / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) is preparing to launch the Index of Services Production (ISP).
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन (ISP) लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
- The ISP will provide a monthly measure of short-term changes in the growth of India's formal services sector.
- ISP भारत के औपचारिक सेवा क्षेत्र की वृद्धि में अल्पकालिक मासिक परिवर्तनों का मापन करेगा।
- The ISP will act as the counterpart of the Index of Industrial Production (IIP) for the services sector.
- ISP सेवा क्षेत्र के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) के समकक्ष सूचकांक के रूप में कार्य करेगा।
- The base year for the ISP has been fixed as 2024–25.
- ISP का आधार वर्ष 2024–25 निर्धारित किया गया है।
- The trial monthly indices for 2025–26 and April 2026 are scheduled to be released on 14th of the next month. Thereafter, the monthly trial indices will be released on the 29th of every month with a lag of about 60 days.
- 2025–26 तथा अप्रैल 2026 के परीक्षण मासिक सूचकांक अगले माह की 14 तारीख को जारी किए जाएंगे। इसके बाद लगभग 60 दिनों की देरी से प्रत्येक माह की 29 तारीख को परीक्षण सूचकांक जारी किए जाएंगे।





News Headlines Related to Ministry :

- Growth in India's Index of Eight Core Industries (ICI) slowed to 0.5% in May 2026, the second-lowest growth recorded in the last 21 months. The data was released by the Ministry of Commerce and Industry.
- भारत के आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (ICI) की वृद्धि दर मई 2026 में घटकर 0.5% रह गई, जो पिछले 21 महीनों में दूसरी सबसे कम वृद्धि है। यह आंकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए।
- The Ministry of Defence is creating seven regional defence manufacturing clusters to strengthen indigenous defence production.
- रक्षा मंत्रालय स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने के लिए सात क्षेत्रीय रक्षा विनिर्माण क्लस्टर स्थापित कर रहा है।
- Union Minister Pralhad Joshi launched the Smart Warehousing System for foodgrain storage at Bharat Mandapam, New Delhi.
- केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में खाद्यान्न भंडारण हेतु स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम का शुभारंभ किया।
- Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare and Rural Development Shivraj Singh Chouhan chaired a meeting of State Rural Development Ministers through video conferencing regarding the implementation of Viksit Bharat – Gramin Bharat (VBG).
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत – ग्रामीण भारत (VBG) के क्रियान्वयन को लेकर राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की।
- The Ministry of Defence (MoD) has granted in-principle approval for a ₹500 crore National Military Drone Technology Hub at IIT Kanpur.
- रक्षा मंत्रालय (MoD) ने IIT कानपुर में ₹500 करोड़ के राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी हब को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
- Union Textiles Minister Giriraj Singh said that India's textile market has grown from about ₹8.5 lakh crore in 2014-15 to over ₹16 lakh crore at present.





Ques: RBI has proposed opening the Term Money Market to which new category of participants?

प्रश्न: RBI ने टर्म मनी मार्केट को किन नए प्रतिभागियों के लिए खोलने का प्रस्ताव दिया है?

- A) Only Cooperative Banks / केवल सहकारी बैंक
- B) NBFCs, HFCs, AIFIs and Companies / NBFCs, HFCs, AIFIs और कंपनियां
- C) Only Insurance Companies / केवल बीमा कंपनियां
- D) Only Foreign Banks / केवल विदेशी बैंक
- E) Only Mutual Funds / केवल म्यूचुअल फंड

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) has proposed allowing a wider set of participants to access the Term Money Market.
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने टर्म मनी मार्केट में अधिक प्रतिभागियों को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।
- Under the proposal, NBFCs, Housing Finance Companies (HFCs), All India Financial Institutions (AIFIs), and companies will be allowed to participate.
- प्रस्ताव के तहत NBFCs, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (AIFIs) और कंपनियों को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
- Currently, only banks and standalone primary dealers are permitted to participate in the Term Money Market.
- वर्तमान में केवल बैंक और स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स को ही टर्म मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति है।
- NBFCs and HFCs (except base-layer NBFCs) will be allowed to both borrow and lend in the market.
- NBFCs और HFCs (बेस-लेयर NBFCs को छोड़कर) को बाजार में उधार लेने और देने दोनों की अनुमति होगी।
- Companies will be permitted to participate as lenders.
- कंपनियों को ऋणदाता (Lenders) के रूप में भाग लेने की अनुमति होगी।
- The proposal aims to deepen market liquidity and strengthen the transmission of monetary policy across different interest-rate tenors.
- इस प्रस्ताव का उद्देश्य बाजार में तरलता (Liquidity) बढ़ाना तथा विभिन्न ब्याज दर अवधियों में मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रसारण को मजबूत करना है।





Ques: Which organization launched the 'PFRDA Pension Sahayak' portal to resolve pension-related issues and complaints more efficiently?

प्रश्न: पेंशन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित और सुगम समाधान के लिए 'PFRDA Pension Sahayak' पोर्टल किस संगठन ने लॉन्च किया?

- A) Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) / कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
- B) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)
- D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (SEBI)
- E) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) launched the 'PFRDA Pension Sahayak' portal.
- पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 'PFRDA Pension Sahayak' पोर्टल लॉन्च किया।
- The portal aims to resolve pension-related issues and complaints faster and in a more seamless manner.
- इस पोर्टल का उद्देश्य पेंशन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों का अधिक तेज़ और सुगम समाधान प्रदान करना है।
- The PFRDA Pension Sahayak portal supports 22 languages, making it accessible to users across the country.
- PFRDA Pension Sahayak पोर्टल 22 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यह देशभर के उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ बन गया है।
- The new portal has replaced the Central Grievance Management System (CGMS).
- इस नए पोर्टल ने Central Grievance Management System (CGMS) का स्थान लिया है।
- The initiative is expected to improve grievance redressal efficiency and enhance the overall experience of pension subscribers.





Recent News Headlines Related to launched Apps/portals :

- Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah launched NAFEX.in, the digital auction portal of National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India.
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NAFED के डिजिटल ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ किया।
- WT-MARUT (Wind Turbine Materials and Resources Utility Tracker) is India's first Wind Turbine Supply Chain Management Portal.
- WT-MARUT (विंड टरबाइन मैटेरियल्स एंड रिसोर्सेज यूटिलिटी ट्रैकर) भारत का पहला पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल है।
- The Union Government has launched an AI-enabled voice chatbot named 'Samadhan Didi' to help citizens register grievances online.
- केंद्र सरकार ने नागरिकों को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए 'समाधान दीदी' नामक एआई-सक्षम वॉयस चैटबॉट लॉन्च किया है।
- India Semiconductor Mission (ISM) under MeitY launched the "Investors Support" portal.
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) ने "Investors Support" पोर्टल लॉन्च किया।
- Union Minister for Social Justice and Empowerment Dr. Virendra Kumar launched the PM-AJAY Portal and AJAY Mobile App.
- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने PM-AJAY Portal और AJAY Mobile App लॉन्च किया।
- Union AYUSH Minister Prataprao Jadhav launched the Ayush Anudan Portal in New Delhi.
- केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने नई दिल्ली में Ayush Anudan Portal का शुभारंभ किया।
- The Union Ministry of Health and Family Welfare launched JANANI (Journey of Antenatal, Natal and Neonatal Integrated Care).





Ques: Which Bengaluru-based fintech company obtained an international payment licence in Canada, marking its first international licence outside India?

प्रश्न: किस बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी ने कनाडा में अंतरराष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस प्राप्त किया, जो भारत के बाहर उसका पहला अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है?

- A) Razorpay / रेज़रपे
- B) Cashfree Payments / कैशफ्री पेमेंट्स
- C) Skydo / स्काईडो
- D) CRED / क्रेड
- E) Pine Labs / पाइन लैब्स

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Bengaluru-based fintech company Skydo obtained an international payment licence in Canada.
- बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी Skydo ने कनाडा में अंतरराष्ट्रीय भुगतान लाइसेंस प्राप्त किया।
- This is Skydo's first international licence outside India.
- यह भारत के बाहर Skydo का पहला अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है।
- The licence will enable the company to expand its cross-border payment operations across Canada and North America.
- इस लाइसेंस से कंपनी कनाडा और उत्तरी अमेरिका में अपनी सीमा-पार (Cross-border) भुगतान सेवाओं का विस्तार कर सकेगी।
- Skydo already has approval to operate from GIFT City, India's International Financial Services Centre (IFSC).
- Skydo को पहले से ही भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) GIFT City से संचालन की अनुमति प्राप्त है।
- GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City), located in Gandhinagar, Gujarat, is India's first operational smart city and International Financial Services Centre.
- GIFT City (Gujarat International Finance Tec-City), गांधीनगर, गुजरात में स्थित भारत का पहला परिचालन स्मार्ट सिटी एवं अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) है।





Ques: Which port became the first major port in India to deploy an enterprise-grade Generative AI platform through a mobile application named PortGPT?

प्रश्न: PortGPT नामक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एंटरप्राइज़-ग्रेड जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बना?

- A) Jawaharlal Nehru Port / जवाहरलाल नेहरू पोर्ट
- B) Deendayal Port / दीनदयाल पोर्ट
- C) Chennai Port / चेन्नई पोर्ट
- D) Paradip Port / पारादीप पोर्ट
- E) V.O. Chidambaranar Port / वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- V.O. Chidambaranar Port Authority, Thoothukudi, Tamil Nadu, launched PortGPT, a dedicated mobile application based on Generative Artificial Intelligence (AI).
- तमिलनाडु के तूतीकोरिन (Thoothukudi) स्थित वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट प्राधिकरण ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित मोबाइल एप्लिकेशन PortGPT लॉन्च किया।
- The application was launched by Union Minister Sarbananda Sonowal.
- इस एप्लिकेशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया।
- With this initiative, V.O. Chidambaranar Port became the first major port in India to deploy an enterprise-grade Generative AI platform through a mobile application.
- इस पहल के साथ वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एंटरप्राइज़-ग्रेड जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म लागू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया।
- The Port Authority also signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Gati Shakti Vishwavidyalaya.
- पोर्ट प्राधिकरण ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए।
- The collaboration aims to promote research, innovation, logistics education, skill development, and sustainable port operations.
- इस सहयोग का उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार, लॉजिस्टिक्स शिक्षा, कौशल विकास तथा सतत बंदरगाह संचालन को बढ़ावा देना है।





Ques: According to PPAC, what was the price of India's Crude Oil Basket on 24 June 2026?

प्रश्न: PPAC के अनुसार 24 जून 2026 को भारत की कूड ऑयल बास्केट की कीमत कितनी थी?

- A) \$60.71 per barrel / \$60.71 प्रति बैरल
- B) \$70.71 per barrel / \$70.71 प्रति बैरल
- C) \$80.71 per barrel / \$80.71 प्रति बैरल
- D) \$90.71 per barrel / \$90.71 प्रति बैरल
- E) \$157.04 per barrel / \$157.04 प्रति बैरल

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- India's Crude Oil Basket price has returned to the level prevailing before the Iran conflict.
- भारत की कूड ऑयल बास्केट की कीमत ईरान संघर्ष से पहले के स्तर पर वापस पहुंच गई है।
- According to the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC), the Indian Crude Basket price declined from a record high of \$157.04 per barrel on 23 March 2026 to \$70.71 per barrel on 24 June 2026.
- पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के अनुसार, भारतीय कूड बास्केट की कीमत 23 मार्च 2026 को \$157.04 प्रति बैरल के रिकॉर्ड उच्च स्तर से घटकर 24 जून 2026 को \$70.71 प्रति बैरल रह गई।
- This represents a decline of nearly 55%, completely reversing the oil price shock caused by the conflict.
- यह लगभग 55% की गिरावट को दर्शाता है, जिससे संघर्ष के कारण उत्पन्न तेल मूल्य झटका पूरी तरह समाप्त हो गया।
- The decline followed the US-Iran peace agreement, which eased concerns regarding disruptions in global oil supplies.
- यह गिरावट अमेरिका-ईरान शांति समझौते के बाद आई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की चिंताएं कम हुईं।
- The conflict had begun on 28 February 2026 after missile strikes raised fears about crude oil supplies from West Asia.
- यह संघर्ष 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब मिसाइल हमलों के कारण पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।





Ques: Adani Airport City Ltd. plans to develop Changi-inspired airport cities across how many states in India?

प्रश्न: अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड भारत में चांगी-प्रेरित एयरपोर्ट सिटी कितने राज्यों में विकसित करने की योजना बना रही है?

- A) 3 States / 3 राज्य
- B) 4 States / 4 राज्य
- C) 5 States / 5 राज्य
- D) 6 States / 6 राज्य
- E) 7 States / 7 राज्य

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Adani Airport City Ltd., a subsidiary of Adani Airport Holdings Ltd., has announced plans to develop integrated Changi-inspired airport cities across its airport network in India.
- अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट सिटी लिमिटेड ने भारत में अपने एयरपोर्ट नेटवर्क पर चांगी-प्रेरित एकीकृत एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की योजना की घोषणा की है।
- The first phase of the project will involve an investment of more than ₹20,000 crore.
- परियोजना के प्रथम चरण में ₹20,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा।
- Around 22 million square feet of development is planned across Mumbai, Navi Mumbai, Ahmedabad, Lucknow, Jaipur and Guwahati.
- मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में लगभग 22 मिलियन वर्ग फुट क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
- The project will be spread over nearly 655 acres across six airports in five states.
- यह परियोजना पांच राज्यों के छह हवाई अड्डों में लगभग 655 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी।
- Nearly 70% of the planned investment will be concentrated in Mumbai and Navi Mumbai.
- प्रस्तावित निवेश का लगभग 70% हिस्सा मुंबई और नवी मुंबई में केंद्रित होगा।
- The airport cities will integrate hospitality, retail, entertainment, convention centres and commercial infrastructure into a single ecosystem.





Ques: Which company is expected to invest around \$370 million in India for manufacturing advanced hybrid powertrains and engines?

प्रश्न: भारत में उन्नत हाइब्रिड पावरट्रेन और इंजन निर्माण के लिए लगभग 370 मिलियन डॉलर का निवेश करने वाली कंपनी कौन है?

- A) BYD Auto / बीवाईडी ऑटो
- B) SAIC Motor / एसएआईसी मोटर
- C) Horse Powertrain / हॉर्स पावरट्रेन
- D) Great Wall Motors / ग्रेट वॉल मोटर्स
- E) Changan Automobile / चांगान ऑटोमोबाइल

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- India is set to approve an investment of around \$370 million by Horse Powertrain, a hybrid-engine venture backed by China's Zhejiang Geely Holding Group.
- भारत चीन की Zhejiang Geely Holding Group समर्थित हाइब्रिड इंजन कंपनी Horse Powertrain के लगभग 370 मिलियन डॉलर के निवेश को मंजूरी देने की तैयारी में है।
- The investment is expected to be one of the largest manufacturing investments from a Chinese-linked company in recent years.
- यह हाल के वर्षों में किसी चीनी-समर्थित कंपनी द्वारा भारत में किए जाने वाले सबसे बड़े विनिर्माण निवेशों में से एक होगा।
- Horse Powertrain is jointly backed by Geely Group and French automobile manufacturer Renault.
- Horse Powertrain को Geely Group और फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी Renault का संयुक्त समर्थन प्राप्त है।
- The proposed investment will support Renault's manufacturing operations in India.
- प्रस्तावित निवेश भारत में Renault के विनिर्माण कार्यों को मजबूत करेगा।
- The approval would be among the first major clearances after India relaxed investment rules for neighbouring countries in March 2026.
- मार्च 2026 में पड़ोसी देशों के लिए निवेश नियमों में ढील दिए जाने के बाद यह पहली बड़ी स्वीकृतियों में से एक होगी।





Ques: As of 22 June 2026, the total area sown under all kharif crops stood at?

प्रश्न: 22 जून 2026 तक सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बुवाई क्षेत्र कितना था?

- A) 8.75 Million Hectares / 8.75 मिलियन हेक्टेयर
- B) 9.50 Million Hectares / 9.50 मिलियन हेक्टेयर
- C) 10.25 Million Hectares / 10.25 मिलियन हेक्टेयर
- D) 11.79 Million Hectares / 11.79 मिलियन हेक्टेयर
- E) 13.50 Million Hectares / 13.50 मिलियन हेक्टेयर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Kharif sowing has been impacted in several parts of India due to delayed and deficient monsoon rainfall.
- मानसून की देरी और कम वर्षा के कारण देश के कई हिस्सों में खरीफ बुवाई प्रभावित हुई है।
- As of 22 June 2026, the total area sown under all kharif crops stood at 11.79 million hectares.
- 22 जून 2026 तक सभी खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बुवाई क्षेत्र 11.79 मिलियन हेक्टेयर रहा।
- Rainfall deficiency during 1–25 June stood at 41.2% below the Long Period Average (LPA) at the all-India level.
- 1–25 जून के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर वर्षा दीर्घकालिक औसत (LPA) से 41.2% कम रही।
- Central India recorded the highest rainfall deficit of 57%, followed by East & Northeast India (42%), South Peninsula (28%), and Northwest India (21%).
- मध्य भारत में सबसे अधिक 57% वर्षा की कमी दर्ज की गई, इसके बाद पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत (42%), दक्षिण प्रायद्वीप (28%) और उत्तर-पश्चिम भारत (21%) रहे।
- Delayed monsoon progress in western and central regions slowed sowing and transplantation of crops such as paddy, pulses, cotton, and oilseeds.
- पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में मानसून की धीमी प्रगति के कारण धान, दलहन, कपास और तिलहन जैसी फसलों की बुवाई एवं रोपाई प्रभावित हुई है।
- The India Meteorological Department (IMD) has forecast favourable conditions for further advancement of the southwest monsoon.
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून की आगे की प्रगति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अनुमान जताया है।





Ques: Amazon has announced an additional investment of how much in India to expand AI and cloud infrastructure?

प्रश्न: AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए अमेज़न ने भारत में कितने अतिरिक्त निवेश की घोषणा की है?

- A) \$5 Billion / 5 अरब डॉलर
- B) \$8 Billion / 8 अरब डॉलर
- C) \$10 Billion / 10 अरब डॉलर
- D) \$13 Billion / 13 अरब डॉलर
- E) \$20 Billion / 20 अरब डॉलर

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Amazon has announced an additional investment of \$13 billion in India.
- अमेज़न ने भारत में अतिरिक्त 13 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है।
- The investment will accelerate the development of Artificial Intelligence (AI) and Cloud Infrastructure in India.
- यह निवेश भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति देगा।
- The fresh investment will expand the Amazon Web Services (AWS) data centre capacity in Mumbai and Hyderabad.
- इस नए निवेश से मुंबई और हैदराबाद में Amazon Web Services (AWS) के डेटा सेंटर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
- Amazon will also establish more than 20 new fulfilment centres and over 100 delivery stations across India this year.
- अमेज़न इस वर्ष भारत में 20 से अधिक नए फुलफिलमेंट सेंटर और 100 से अधिक डिलीवरी स्टेशन भी स्थापित करेगा।
- Earlier, Amazon had already pledged investments of more than \$35 billion in India by 2030.
- इससे पहले अमेज़न 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर से अधिक निवेश की घोषणा कर चुका है।
- With the new commitment, Amazon's cumulative investments in India (2010–2030) are expected to exceed \$88 billion.





Ques: Who became the first cricketer in the history of both men's and women's cricket to play 200 Twenty20 International (T20I) matches?

प्रश्न: पुरुष एवं महिला दोनों क्रिकेट के इतिहास में 200 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनीं?

- A) Smriti Mandhana / स्मृति मंधाना
- B) Ellyse Perry / एलिस पेरी
- C) Suzie Bates / सूजी बेट्स
- D) Harmanpreet Kaur / हरमनप्रीत कौर
- E) Danni Wyatt-Hodge / डैनी वायट-हॉज

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- Indian captain Harmanpreet Kaur created history by becoming the first cricketer in both men's and women's cricket to play 200 Twenty20 International (T20I) matches.
- भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर पुरुष एवं महिला दोनों क्रिकेट के इतिहास में 200 ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बनीं।
- She achieved this milestone during India's match against South Africa in the ICC Women's T20 World Cup 2026 at Old Trafford, Manchester.
- उन्होंने यह उपलब्धि ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में हासिल की।
- Harmanpreet made her international debut in March 2009 in a One Day International (ODI) against Pakistan.
- हरमनप्रीत ने मार्च 2009 में पाकिस्तान के खिलाफ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय (ODI) मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की।
- The leading players in terms of T20I appearances are: Harmanpreet Kaur (200), Suzie Bates (184), Danni Wyatt-Hodge (183), Ellyse Perry (177), and Smriti Mandhana (169).
- T20I मैचों में सर्वाधिक उपस्थिति वाले खिलाड़ियों में हरमनप्रीत कौर (200), सूजी बेट्स (184), डैनी वायट-हॉज (183), एलिस पेरी (177) और स्मृति मंधाना (169) शामिल हैं।





Recent News headlines related to Sports

- Argentine football legend Lionel Messi became the first player in history to appear in six FIFA World Cups after featuring in Argentina's opening match against Algeria in the FIFA World Cup 2026.
- अर्जेटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने छह फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है; उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेटीना के शुरुआती मैच में खेलकर यह उपलब्धि हासिल की।
- Argentina defeated Austria 2-0 in their Group J match of the FIFA World Cup 2026.
- फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप J मुकाबले में अर्जेटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया।
- India's teenage batting sensation Vaibhav Sooryavanshi created history by smashing the fastest half-century in List A cricket.
- भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट-A क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक लगाकर इतिहास रच दिया।
- India's Abhay Singh and Velavan Senthilkumar won the Men's Doubles title at the 3rd Asian Doubles Championships 2026. Squash The tournament was held in Sarawak, Malaysia. Runners-up are Nasir Iqbal & Noor Zaman (Pakistan).
- भारत के अभय सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार ने तीसरी एशियन डबल्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का डबल्स खिताब जीता। यह स्वदेश टूर्नामेंट मलेशिया के सारावाक में आयोजित किया गया था। इसमें पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर ज़मान रनर-अप रहे।
- England's Joe Root crossed the 14,000-run milestone in Test cricket during the second Test against New Zealand.
- इंग्लैंड के जो रूट ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा पार किया।
- India Women's National Field Hockey Team defeated New Zealand Women's National Field Hockey Team by 2-0 in the final of the FIH Women's Nations Cup 2026 held in Auckland.
- भारत की महिला हॉकी टीम ने न्यूज़ीलैंड को 2-0 से हराकर FIH महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता।





Ques: Till which date has the Ministry of Heavy Industries extended the bid submission deadline for the ₹7,280 crore Rare Earth Magnet Manufacturing Scheme?

प्रश्न: भारी उद्योग मंत्रालय ने ₹7,280 करोड़ की रेयर अर्थ मैग्नेट विनिर्माण योजना के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि किस दिन तक बढ़ाई है?

- A) 15 July 2026 / 15 जुलाई 2026
- B) 20 July 2026 / 20 जुलाई 2026
- C) 29 July 2026 / 29 जुलाई 2026
- D) 30 July 2026 / 30 जुलाई 2026
- E) 15 August 2026 / 15 अगस्त 2026

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Heavy Industries (MHI) has extended the bid submission deadline for the ₹7,280 crore Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets (REPM).
- भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने ₹7,280 करोड़ की सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (REPM) विनिर्माण प्रोत्साहन योजना के लिए बोली जमा करने की समय-सीमा बढ़ा दी है।
- The extension was granted after multiple stakeholders requested additional time to prepare bids.
- कई हितधारकों द्वारा बोली तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग किए जाने के बाद यह विस्तार दिया गया है।
- Earlier, the deadline had been extended from 28 May to 29 June 2026.
- इससे पहले अंतिम तिथि 28 मई से बढ़ाकर 29 जून 2026 की गई थी।
- Under the revised schedule, bids can now be submitted until 29 July 2026.
- संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब बोलियां 29 जुलाई 2026 तक जमा की जा सकेंगी।
- Technical bids will now be opened on 30 July 2026 instead of 30 June 2026.
- तकनीकी बोलियां अब 30 जून 2026 के स्थान पर 30 जुलाई 2026 को खोली जाएंगी।
- Industry stakeholders had raised concerns regarding limited raw material allocation and incentive criteria linked to magnet weight instead of quality.





Ques: Samvidhaan Hatya Diwas is observed every year on which date?

प्रश्न: संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है?

- A) 23 June / 23 जून
- B) 24 June / 24 जून
- C) 25 June / 25 जून
- D) 26 June / 26 जून
- E) 21 March / 21 मार्च

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Samvidhaan Hatya Diwas is observed every year on 25 June to commemorate the declaration of the National Emergency on 25 June 1975 and to remember those who suffered during the Emergency period.
- संविधान हत्या दिवस प्रतिवर्ष 25 जून को 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की स्मृति तथा आपातकाल के दौरान कष्ट झेलने वाले लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है।
- On the night of 25 June 1975, President Fakhruddin Ali Ahmed proclaimed a National Emergency under Article 352 of the Constitution on the advice of Prime Minister Indira Gandhi.
- 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति फ़ख़रुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
- The Emergency remained in force from 25 June 1975 to 21 March 1977.
- राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा।
- The Emergency period witnessed the suspension of several Fundamental Rights, censorship of the press and large-scale political arrests.
- आपातकाल के दौरान कई मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लागू की गई तथा बड़े पैमाने पर राजनीतिक गिरफ्तारियाँ हुईं।

Static Part | स्थैतिक जानकारी:

- Article 352 deals with the Proclamation of National Emergency.
- अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है।





- There are three types of Emergencies under the Constitution of India: National Emergency (Article 352), State Emergency/President's Rule (Article 356), and Financial Emergency (Article 360).
- भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है—राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल/राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) तथा वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
- The 44th Constitutional Amendment Act, 1978 introduced important safeguards relating to the proclamation of National Emergency.
- 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान जोड़े गए।
- Article 352 can be invoked on the grounds of War, External Aggression or Armed Rebellion.
- अनुच्छेद 352 युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया जा सकता है।

EXAM
Genius





Important days :

- 1 June : Global Day of Parents (Theme for 2026: "Together for Parents".)
- 1 June : World Milk Day (Theme 2026 Celebrating Women Farmers) (Started in 2001 by the Food and Agriculture Organization (FAO))
- 2 June : Telangana celebrated its 11th State Formation Day
- 2 June : International Sex Workers' Day 2026 (Theme 2026 Access to Justice)
- 3 June : world bicycle day (Theme "Cycling for a Greener Future.")
- 4 June : International Day of Innocent Children Victims of Aggression (Started in 1982)
- 5 June : World Environment Day (Theme 2026 is "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future".)
- 5 June : The International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing
- 6 June : Russian Language Day
- 6 June : World Pest Day (Theme 2026 Defending Health Across Borders: The Global Power of Pest Management)
- 7 June : World Food Safety Day 2026 (Theme "From Burden to Solutions – Safe Food Everywhere")
- 8 June : World Oceans Day (The Action Theme for 2026 is "Strong Marine Protected Areas for Our Blue Planet", led by the World Ocean Day Network) (The Core Theme designated by the United Nations World Oceans Day is "Reimagine: Beyond the world we know, a new relationship with our ocean.")
- 8 June : World Brain Tumor Day 2026 (Started in 2000) (Symbol is Grey Ribbon)
- 9 June : 18th International Level Crossing Awareness Day (ILCAD) 2026 (slogan for ILCAD 2026 was "Alert Today, Safe Tomorrow".)
- 9 June : International Archives Day 2026 (Theme 2026 #ArchivesForJustice: Rights, Memory & Futures)
- 10 June : International Day for Dialogue among Civilizations
- 11 June : International Day of Play (Started on June 11, 2024) (Theme 2026 Protect Play, Protect Childhood)
- 12 June : World Day Against Child Labour (theme for 2026 is "Red Card to Child Labour: Fair Play for Children, Decent Work for Adults.")





IMPORTANT ONE - LINER Current Affairs

Osmania University, Hyderabad, has become the first university in India to be awarded four internationally recognized ISO Management System Certifications simultaneously by the Bureau of Indian Standards (BIS)

Sanjay Kumar Jain Resigned as Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) Chairman and Managing Director

Government of India will divest up to 2% stake in Indian Railway Finance Corporation through an Offer for Sale (OFS). 1% equity stake as the base offer. 1% additional stake through the Green Shoe Option.

The United States has announced a \$230 million sustainment package for India's M777A2 Ultra-Light Howitzers.

IIT Ropar has secured two prestigious defence technology projects from the 27th Army Technology Board (ATB). The projects have a combined cost of Rs.120 crore.





महत्वपूर्ण वन-लाइनर करंट अफेयर्स

हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) से एक साथ चार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ISO मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई है।

संजय कुमार जैन ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया है।

भारत सरकार 'ऑफ़र फ़ॉर सेल' (OFS) के ज़रिए इंडियन रेलवे फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन में 2% तक हिस्सेदारी बेचेगी। इसमें 1% इक्विटी हिस्सेदारी बेस ऑफ़र के तौर पर और 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी 'ग्रीन शू ऑप्शन' के ज़रिए बेची जाएगी।

अमेरिका ने भारत के M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्ज़र के लिए 230 मिलियन डॉलर के सस्टेनमेंट पैकेज की घोषणा की है।

IIT रोपड़ को 27वें आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड (ATB) से दो प्रतिष्ठित डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मिले हैं। इन प्रोजेक्ट्स की कुल लागत 120 करोड़ रुपये है।

